



दैनिक बुद्ध का संदेश

हिन्दी समाचार पत्र

शिमरी साड़ी पहन
अमावसा दस्तूर ने ...8

बलरामपुर

गुरुवार , 04 जून 2026

वर्ष: 05 अंक : 243 पृष्ठ: 8

आमंत्रण मूल्य 2/-रुपया

एक विश्वास...

सम्पादक : राजेश शर्मा

9415163471, 9453824459 Dainik Budh ka sandesh @budhakasandesh budhakasandeshnews@gmail.com www.budhakasandesh.com

जनपद में बड़ा हादसा निर्माणाधीन गेट गिरने से एक मजदूर की मौत, छह घायल

हादसे को ले कर जाँच समिति का गठन, 03 दिन में देंगे रिपोर्ट

दैनिक बुद्ध का संदेश



शोहरतगढ़ / सिद्धार्थनगर। बढनी ब्लॉक क्षेत्र के मधवापुर में निर्माणाधीन मछली मंडी का गेट बुधवार को अचानक भरभराकर गिर गया। हादसे में एक मजदूर की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि छह अन्य श्रमिक घायल हो गए। घटना के बाद क्षेत्र में शोक और आक्रोश का माहौल है। मामले को लेकर शोहरतगढ़ विधायक विनय वर्मा ने जिलाधिकारी सिद्धार्थनगर को पत्र भेजकर उच्चस्तरीय मजिस्ट्रेटी जांच, दोषियों के खिलाफ एफआईआर, मृतक के परिजनों को मुआवजा और घायलों के समुचित उपचार की मांग की है। विधायक ने अपने पत्र में कहा है कि लगभग 5.56 करोड़ रुपये की लागत से निर्माणाधीन मछली मंडी के कार्य में अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और निम्न गुणवत्ता की शिकायतें वह समय-समय पर उठाते रहे हैं, लेकिन प्रशासन ने उन्हें गंभीरता

से नहीं लिया। उनका कहना है कि बिना किसी अंधी, तूफान अथवा प्राकृतिक आपदा के निर्माणाधीन गेट का गिर जाना कार्य में मानकों की अनदेखी और गुणवत्ताहीन सामग्री के प्रयोग की ओर संकेत करता है। उन्होंने कहा कि गत 19 मई को जिलाधिकारी स्वयं मछली मंडी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर चुके थे। इसके बावजूद स्थानीय नागरिकों द्वारा लगातार दी जा रही शिकायतों को नजरअंदाज किया गया। क्षेत्र के लोगों का आरोप था कि निर्माण कार्य में मानकों की घोर अनदेखी की जा रही है तथा गुणवत्ताहीन सामग्री का प्रयोग हो रहा है। विधायक ने कहा कि यदि निर्माण कार्य निर्धारित मानकों के अनुरूप करया गया होता तो यह हादसा नहीं होता। विधायक ने दुर्घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों

के मौके पर देर से पहुंचने पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी घटना के बावजूद करीब दो से ढाई घंटे तक जिला प्रशासन अथवा तहसील प्रशासन का कोई जिम्मेदार अधिकारी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा। समय पर राहत एवं बचाव कार्य नहीं होने के कारण एक मजदूर लंबे समय तक मलबे में दबा रहा, जिससे उसकी मौत हो गई। उन्होंने इसे जिला प्रशासन की लापरवाही, अकर्मण्यता और संवेदनहीनता का उदाहरण बताया। पत्र में विधायक ने कहा है कि सड़क निर्माण, स्टेडियम,

कटानरोधी कार्यों और सिंचाई परियोजनाओं समेत विभिन्न विकास कार्यों में भी वह लगातार अनियमितताओं, भ्रष्टाचार और गुणवत्ता संबंधी शिकायतें प्रशासन के संज्ञान में लाते रहे हैं, लेकिन कार्रवाई की जाए। मृतक मजदूर के परिजनों को उचित मुआवजा दिया जाए तथा घायलों के सर्वोत्तम उपचार और पर्याप्त आर्थिक सहायता की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। साथ ही समस्त निर्माण कार्यों की गुणवत्ता की जांच कर दोषी अधिकारियों और ठेकेदारों की जिम्मेदारी तय की जाए। विधायक ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार भ्रष्टाचारमुक्त प्रशासन, सुशासन और गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है, लेकिन कुछ अधिकारियों की लापरवाही और गैर-जिम्मेदाराना रवैये से सरकार की मंशा को बार-बार ठेस पहुंच रही है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि मछली मंडी निर्माण में लापरवाही बरतने वाले दोषियों पर तत्काल कार्रवाई की जाए और पूर्व में उठाए गए अन्य मामलों की गंभीरता से जांच कराई जाए।

दक्षिण दिल्ली के एक इलाके में स्थित पांच मंजिला इमारत में एक बेड-एंड-ब्रेकफास्ट में भीषण आग लग गई, जिसमें कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई

रेस्तेरेंट में आग लगने से 21 की मौत

गैरइरादतन हत्या का मामला दर्ज, हिरासत में मालिक

जानकारी की तलाश कर रहे थे। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस घटना के बाद दिल्ली अग्निशमन सेवा (डीएफएस) द्वारा बड़े पैमाने पर बचाव अभियान

त्वरित प्रतिक्रिया वाहन और अन्य आपातकालीन उपकरण शामिल थे। दिल्ली अग्निशमन सेवा के एक अधिकारी ने बताया कि लेमन ग्रीन रेस्तरां के तहखाने से तीन लोगों को बचाया गया। आग पर काबू पाने के लिए सुबह करीब 8:50 बजे कई अग्निशमन गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। बचाए गए लोगों को सीएटीएस एम्बुलेंस से अस्पताल ले जाया गया। उनकी हालत के बारे में तत्काल जानकारी नहीं मिल पाई है। आग लगने का सटीक कारण अभी तक पता



और कई अन्य घायल हो गए। मृतकों में से कई विदेशी नागरिक थे। कई घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया। अधिकारियों ने बताया कि ये विदेशी नागरिक मुख्य रूप से मध्य एशियाई और अफ्रीकी देशों के थे। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। इस बीच, कम से कम 21 लोगों की मौत के घंटों बाद भी शोक संतप्त रिश्तेदार साकेत स्थित मैक्स अस्पताल में जमा होकर अपने प्रियजनों के बारे में

चलाया गया। दिल्ली के मालवीय नगर स्थित रेस्तरां में आग खबर एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मालवीय नगर के घनी आबादी वाले इलाके हौज रानी में स्थित प्लोरिश स्टे बीएंडबी में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली अग्निशमन सेवा को सुबह आपातकालीन सूचना मिली और उन्होंने तुरंत कई अग्निशमन दल मौके पर भेजे। इस दल में दो पानी की गाड़ियां, दो पानी के टैंकर, एक

नहीं चल पाया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है। आग लगने की घटना में एफआईआर दर्ज: अधिकारियों ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने होटल में लगी आग की घटना में गैर इरादतन हत्या के आरोप में एफआईआर दर्ज की है। पुलिस सूत्रों ने समाचार एजेंसी पीटीआई को बताया कि होटल में प्रवेश और निकास का केवल एक ही द्वार था। उन्होंने कहा कि अग्निशमन संबंधी एनओसी की जांच की जा रही है।

विकास भवन में डीएम का औचक निरीक्षण, बड़ी संख्या में अधिकारी-कर्मचारी मिले अनुपस्थित

दैनिक बुद्ध का संदेश

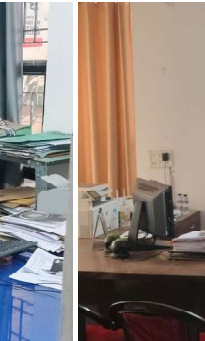


सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने बुधवार को पूर्वाह्न 10:25 बजे विकास भवन स्थित विभिन्न विभागीय कार्यालयों का औचक निरीक्षण कर कर्मचारियों की उपस्थिति

और कार्य व्यवस्था का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान कई विभागों में अधिकारी और कर्मचारी अनुपस्थित पाए गए, जिस पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की। निरीक्षण में उपायुक्त

श्रम रोजगार संतोष कुमार चौधरी तथा अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी मनरेगा सहित विभिन्न विभागों के अनेक अधिकारी, वरिष्ठ सहायक, कनिष्ठ सहायक, वाहन चालक और चतुर्थी श्रेणी कर्मचारी

को जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी डीआरडी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परियोजना अधिकारी डूडा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं



कार्यालय से गायब रहने वाले अधिकारी

जलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. के निरीक्षण में जिला ग्रामोद्योग, डूडा, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पंचायत राज, कार्यक्रम अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागों के कई कर्मचारी भी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी को जिला विकास अधिकारी, परियोजना अधिकारी डीआरडी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, परियोजना अधिकारी डूडा, जिला पंचायत राज अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, सहायक निदेशक बचत, सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबंधक सहकारिता, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य सहित कई विभागाध्यक्ष अधिकारी भी अनुपस्थित मिले।



बिना अनुमति अनुपस्थित मिले। इसके अलावा जिला ग्रामोद्योग, डूडा, लघु सिंचाई, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, पंचायत राज, कार्यक्रम अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण तथा दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभागों के कई कर्मचारी भी कार्यालय में उपस्थित नहीं थे। जिलाधिकारी

संख्याधिकारी, सहायक निदेशक बचत, सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबंधक सहकारिता, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, सहायक निदेशक मत्स्य सहित कई विभागाध्यक्ष भी अनुपस्थित मिले। वहीं पंचास्थानी नगरीय निकाय कार्यालय में निरीक्षण के समय कोई भी कर्मचारी उपस्थित



नहीं पाया गया, जिसे डीएम ने गंभीर लापरवाही माना। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यालयों में समय से उपस्थिति और जनहित के कार्यों का नियमित संचालन

सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने अनुपस्थित पाए गए सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों का 03 जून 2026 का वेतन बाधित करने का आदेश दिया तथा निर्देशित

किया कि सभी संबंधित कर्मचारी और अधिकारी दो कार्य दिवस के भीतर अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें। डीएम ने स्पष्ट किया कि शासकीय कार्यों में लापरवाही और

अनुशासनहीनता किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी तथा भविष्य में भी इसी प्रकार औचक निरीक्षण जारी रहेंगे। अनुपस्थित कर्मियों के स्पष्टीकरण के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

स्काउट-गाइड प्रशिक्षण के तीसरे दिन स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं सेवा भाव पर दिया गया जोर

दैनिक बुद्ध का संदेश

श्रावस्ती। जगतजीत इंटर कॉलेज, इकौना में चल रहे स्काउट-गाइड प्रशिक्षण शिविर के तीसरे दिन प्रशिक्षार्थियों को



स्वास्थ्य, स्वच्छता, अनुशासन एवं सेवा भावना का महत्व बताया गया। प्रशिक्षण प्रभारी कामाछा प्रसाद पाठक ने कहा कि स्काउट एवं गाइड युवाओं में उत्तम स्वास्थ्य, अनुशासन और चरित्र निर्माण का एक सशक्त माध्यम है। यह उन्हें शारीरिक रूप से मजबूत और मानसिक रूप से सतर्क बनाता है तथा समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है। उन्होंने बताया कि

स्काउट्स और गाइड्स को प्राथमिक चिकित्सा (फर्स्ट एड) का विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है, जिससे वे चोट, दुर्घटना

योगदान देते हैं। इसके साथ ही वे स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित विशेष टीकाकरण कार्यक्रमों, पल्स पोलियो अभियान तथा स्वास्थ्य जागरूकता कार्यक्रमों में भी सक्रिय सहभागिता निभाते हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण के दौरान नियमित व्यायाम, पीटी, योगासन एवं आउटडोर खेलों को शामिल किया गया है, जिससे विद्यार्थियों की शारीरिक क्षमता, सहनशक्ति एवं नेतृत्व कौशल का विकास हो सके। बाद, भूकंप एवं महामारी जैसी आपदाओं के दौरान भी स्काउट-गाइड दल राहत एवं बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तथा जरूरतमंद लोगों तक सहायता पहुंचाने में सहयोग करते हैं। इस अवसर पर हनुमान प्रसाद सहित स्काउट-गाइड के छात्र-छात्राएं उपस्थित रहे।यह स्क्रिप्ट समाचार पत्र में प्रकाशन के लिए उपयुक्त शैली में तैयार की गई है।

थाना दुधारा कड़जा में “साइबर जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का हुआ आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश

संत कबीरनगर। पुलिस अधीक्षक संदीप कुमार मीना के निर्देशन, अपर पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार सिंह के मार्गदर्शन तथा क्षेत्राधिकारी साइबर क्राइम अमित कुमार के पर्यवेक्षण में साइबर अपराधों की रोकथाम एवं आमजन को डिजिटल सुरक्षा के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से साइबर थाना प्रभारी जयप्रकाश चौबे एवं साइबर थाने की टीम द्वारा थाना दुधारा क्षेत्रान्तर्गत कड़जा में साइबर जागरूकता एवं साइबर सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया गया।। गोष्ठी के दौरान लोगों को अज्ञात कॉल, लिंक, ई-मेल, लॉटरी ऑफर, व्‍यूआर कोड स्कैन, फेक क्रेडिट, वर्क फ्रॉम होम, पुलिस इमपरशोनेशन,

APK फाइल आदि के माध्यम से की जाने वाली धोखाधड़ी से सतर्क रहने हेतु बताया गया



साथ ही यह भी अवगत कराया गया कि किसी भी प्रकार की साइबर ठगी अथवा ऑनलाइन अपराध की सूचना तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दें अथवा cybercrime-gov.पद पोर्टल पर शिकायत दर्ज करें।

साइबर अपराधियों द्वारा अनेक प्रलोभन के माध्यम से लाभार्थियों को कॉन्फ्रेंस कॉल पर लेकर

अपराधों के विभिन्न तरीकों एवं उनसे बचाव के उपायों की विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया गया उनसे अपील की गई कि वे अपने बैंक विवरण, ओटीपी, पासवर्ड अथवा किसी भी प्रकार की व्यक्तिगत जानकारी किसी के साथ साझा न करें तथा सोशल मीडिया पर प्राप्त संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें। इस गोष्ठी का उद्देश्य साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा डिजिटल माध्यमों का सुरक्षित उपयोग करने हेतु प्रेरित करना रहा। इस दौरान प्रभारी निरीक्षक साइबर क्राइम थाना जय प्रकाश चौबे, उ0नि0 रमेश यादव, म0का0 अमृता सिंह सहित अन्य अधिकारी /कर्मचारीगण मौजूद रहे।

सिरसी का ग्रामीण मिनी स्टेडियम

खिलाडियों के लिए बनकर तैयार

दैनिक बुद्ध का संदेश

संत कबीर नगर। जिला युवा कल्याण अधिकारी रामप्रताप सिंह ने बताया कि ग्राम पंचायत सिरसी विकास खंड हैसर बाजार, तहसील और

बताया कि ग्रामीण मिनी स्टेडियम को गुणवत्तापूर्ण बनाया गया है और इस दृष्टि से मुख्य विकास अधिकारी और जिलाधिकारी द्वारा भी नियमित

बालक और बालिकाओं के लिए अलग – अलग टॉयलेट के साथ ही चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं। स्टेडियम के बाउंड्री वॉल के अंदर फुटबॉल ,वॉलीबॉल ,क्रिकेट , रनिंग इवेंट एवं अन्य आउटडोर स्पोर्ट्स भी खेले जा सकते हैं।तीन एकड़ में निर्मित ग्रामीण मिनी स्टेडियम सड़क मार्ग से जुड़ा हुआ है और इसके आस-पास के सैकड़ों गांवों के युवाओं को इससे लाभ मिलेगा। स्टेडियम का संचालन युवा कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस वित्तीय वर्ष में स्टेडियम में खेल प्रशिक्षक का भी चयन किया जाएगा। स्टेडियम की 24 घंटे सुरक्षा के लिए 6 पी आर डी जवान भी तैनात किए गए हैं। जनपद के ग्राम पंचायत चन्दनी, विकास खंड बघौली ,विधान सभा मेहदावल में एक अन्य ग्रामीण स्टेडियम निर्मित किया जा रहा है जो अगले वर्ष तक बनकर तैयार हो जाएगा।



विधान सभा धनघटा में युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा ग्रामीण मिनी स्टेडियम बनकर तैयार हो गया है। इस स्टेडियम को बनाने में लगभग 5 करोड़ रुपये खर्च किये गए। इसका निर्माण कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड ने किया है। उन्होंने

निरीक्षण किया गया है। इस स्टेडियम में इनडोर और आउटडोर दोनों प्रकार के स्पोर्ट्स के खेलने की व्यवस्था है। मल्टीपरपज हॉल में बैडमिंटन ,कुश्ती ,कबड्डी आदि गेम खेले जा सकते हैं , वहीं उसी बिल्डिंग के ऊपरी तल पर एक कमरा टेबल टेनिस के लिए भी बनाया गया है।

हरे सागौन के पेड़ कटवाने का आरोप, अधिकारियों ने जांचोपरांत कार्यवाही का दिया आश्वासन

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। गोन्डा वन प्रभाग अन्तर्गत कटरा वन रेंज में लगातार अवैध कटान की खबरें प्रकाशित हो रही हैं जबकि कार्यवाही जो चर्चा है कि कार्यवाही न होने का नतीजा है अवैध प्रतिबंधित वृक्षों की कटान। प्राप्त सूचना के अनुसार विकास खंड कटरा बाजार के थाना



न तो वन विभाग की ओर से कोई रोक-टोक की गई और न ही स्थानीय प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लिया।इससे पेड़ों की अवैध कटान को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं।स्थानीय लोगों का कहना है कि हरे पेड़ों की कटाई पर्यावरण संरक्षण नियमों के विरुद्ध है,फिर भी जिम्मेदार अधिकारियों की चुप्पी संदेह पैदा कर रही है।ग्रामीणों ने मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर

कार्रवाई की मांग की है।ग्रामीणों का आरोप है कि यदि समय रहते जिम्मेदार विभाग कार्रवाई करता तो पेड़ों को बचाया जा सकता था।अब पेड़ों की कटान के बाद प्रशासनिक उदासीनता चर्चा का विषय बनी हुई है।क्षेत्रीय नागरिकों ने जिला प्रशासन एवं वन विभाग के उच्चाधिकारियों से मामले की जांच कराकर अवैध कटान में शामिल लोगों तथा यदि किसी अधिकारी-कर्मचारी की भूमिका सामने आती है तो उनके विरुद्ध भी कार्रवाई किए जाने की मांग की है।इस सम्बन्ध में दूरभाष पर वन क्षेत्र कटरा के अधिकारी इमरान खान से बात की गई तो बताया कि सूचना मिली है मौके पर वन कर्मचारी को भेजा गया है जांच करवाकर उचित कार्यवाही की जाएगी

पयागपुर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, ट्रेन की चपेट में आने से व्यक्ति की मौत

दैनिक बुद्ध का संदेश



बहराइच। पयागपुर रेलवे स्टेशन पर बुधवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। ट्रेन संख्या 05131 गोरखपुर-बहराइच इंटरसिटी एक्सप्रेस की चपेट में आने से एक व्यक्ति की मौके पर ही कटकर मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही रेलवे और स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची तथा शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कार्रवाई शुरू कर दी। समाचार लिखे जाने तक मृतक

की पहचान नहीं हो सकी थी। साथ ही यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि हादसा किन परिस्थितियों में हुआ। पुलिस मृतक की शिनाख्त कराने और घटना के कारणों की जांच में जुटी हुई है। हादसे के बाद स्टेशन परिसर में कुछ समय के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा। ईश्वर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिजनों को इस दुःख की घड़ी में संबल दें।

परिवहन विभाग द्वारा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का किया निरीक्षण, सुरक्षा उपायों को लेकर किया गया स्थलीय मूल्यांकन

दैनिक बुद्ध का संदेश

गोन्डा। गोन्डा जनपद में सड़क सुरक्षा को और अधिक प्रभावी बनाने तथा दुर्घटनाओं में कमी लाने के उद्देश्य से एआरटीओ (प्रशासन/प्रवर्तन) आर.सी. भारतीय के नेतृत्व में

उपलब्धता,सड़क चिन्हांकन, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाओं का अवलोकन किया।स्थानीय नागरिकों एवं वाहन चालकों से संवाद कर दुर्घटनाओं के



परिवहन विभाग की टीम द्वारा जनपद के दुर्घटना बाहुल्य एवं दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया गया।निरीक्षण के दौरान बरदही बाजार एवं बरगदी मोड़, कर्नलगंज स्थित प्रमुख ब्लैक स्पॉट क्षेत्रों का गहन मूल्यांकन किया गया।निरीक्षण के दौरान टीम ने सड़क की भौतिक स्थिति,यातायात दबाव,मोड़ों की संरचना,संकेतक बोर्डों की

संभावित कारणों और आवश्यक सुधारात्मक उपायों के संबंध में जानकारी प्राप्त की गई।एआरटीओ आर.सी. भारतीय ने बताया कि बरदही बाजार एवं बरगदी मोड़ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ यातायात का दबाव अपेक्षाकृत अधिक रहता है तथा पूर्व में भी सड़क दुर्घटनाओं की घटनाएं सामने आई हैं।ऐसे स्थानों की पहचान कर उनका तकनीकी परीक्षण

बस और ई-रिक्शा भिड़त में एक की मौत एक घायल,बस को पुलिस ने लिया कब्जे

दैनिक बुद्ध का संदेश



गोन्डा। गोन्डा जनपद में मंगलवार को देर शाम हुए एक सड़क हादसे में एक महिला की मौत हो गई,जबकि एक व्यक्ति घायल हो गया।लोगों से प्राप्त सूचना के अनुसार घटना नगर कोतवाली क्षेत्र के गोंडा-अयोध्या हाइवे पर ठाकुर द्वारा के पास हुई।एक रोडवेज बस ने ई-रिक्शा को टक्कर मार दी,जिससे वह पलट गया।मृतका की पहचान बनकटावा निवासी 30 वर्षीय इशरत जहां के रूप में हुई है।घायल व्यक्ति पेरी पोखर गांव का निवासी रईस पुत्र बकरीद है, जिसका गोंडा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है।बताया जा रहा है कि अयोध्या की तरफ से गोन्डा आ रही आलम बाग डिपो की रोडवेज बस ने पीछे से ई-रिक्शा को टक्कर मारी थी।टक्कर के बाद ई-रिक्शा पलट गया और इशरत जहां व रईस सड़क पर गिर गए। घटना स्थल पर भीड़ जमा

हो गई।सूचना मिलने पर सद्भावना चौकी प्रभारी विभु तिवारी मौके पर पहुंचे और घायलों को मेडिकल कॉलेज भिजवाया। चिकित्सकों ने इशरत जहां को मृत घोषित कर दिया। इशरत जहां की शादी लखनऊ के बाईपास इमामबाड़ा निवासी मैनुहीन से हुई थी,वह मंगलवार को अपने मायके से भारतीय स्टेट बैंक आने के लिए ई-रिक्शा से जा रही थीं,तभी यह हादसा हो गया।हादसे के बाद अयोध्या मार्ग पर ठाकुर द्वारा से मुन्ना खा चौराहे तक करीब एक घंटे तक लंबा जाम लगा रहा, जिससे लोगों को परेशानी हुई।नगर कोतवाल ने बताया कि रोडवेज बस को कब्जे में ले लिया गया है और मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों की तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

खुटेहना-हुजूरपुर मार्ग पर जानलेवा गड्ढा, बड़े हादसे की आशंका

दैनिक बुद्ध का संदेश



अब तक कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है। बरसात का मौसम नजदीक होने से लगातार कटाव बढ़ने की आशंका है, जिससे स्थिति और अधिक गंभीर हो सकती है। ग्रामीणों और राहगीरों ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि शिकायतों के बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा है। लोगों का कहना है कि विभाग किसी बड़ी दुर्घटना का इंतजार करता नजर आ रहा है। क्षेत्रवासियों ने प्रशासन और लोक निर्माण विभाग से तत्काल सड़क की मरम्मत कराने तथा आवश्यक सुरक्षा इंतजाम करने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते कार्रवाई नहीं हुई तो यह गड्ढा किसी बड़े हादसे का कारण बन सकता है। “गड्ढा बढ़ता जा रहा है और जिम्मेदार विभाग अब भी मौन है,” यह बात स्थानीय लोगों की चिंता और नाराजगी को साफ तौर पर दर्शाती है।

धनराज मौर्य की हत्या में वांछित अभियुक्त आसिफ को गिरफ्तार कर भेजा गया जेल

दैनिक बुद्ध का संदेश
उतरीला / बलरामपुर। कोतवाली क्षेत्र के बमनी बुजुर्ग अहिरोला



में हिंसा के फरार आरोपी आसिफ निवासी पिपराराम को पुलिस ने गिरतार कर लिया है। पुलिस का कहना है कि गिरतारी के दौरान भागते समय गिर जाने के कारण उसके पैर में चोट आई है जिसका इलाज जिला चिकित्सालय में कराया जा रहा है। हालांकि स्थानीय लोगों का आरोप है कि अभियुक्त शुरू से ही पुलिस व एक विभागीय कर्मियों के संपर्क में थे। आसिफ को न्यायालय में आत्मसमर्पण कराने की जुगत की जा रही थी। हिंदू संगठनों के दबाव के चलते उसे गिरतार कर जेल भेजा गया है। मृतक के परिजन व ग्रामीण गैडस बुजुर्ग व उतरीला की पुलिस की कार्रवाई पर शुरू से ही सवालिया निशान लगाते आ रहे हैं। रविवार को भी पुलिस की लीपापोती की कार्रवाई से नाराज लोगों ने बस्ती राजमार्ग पर जाम लगाकर पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की थी। थानाध्यक्ष राजीव मिश्र का कहना है कि आरोपी की तलाश में पुलिस की चार टीमें लगाई गई थीं और उसे बुधवार को मुखविर की सूचना पर गिरतार कर लिया गया।



दैनिक बुद्ध का संदेश

उतरीला / बलरामपुर। बुधवार को अहिरोला मे हिंसा में मृत धनराज मौर्य के परिजनों से मुलाकात के लिए प्रगतिशील विक्रमादित्य मौर्य संगठन के सैकड़ों सदस्य गांव में पहुंचे। शोक संतप्त परिजनों को दिलासा देते हुए प्रशासन की गैर जिम्मेदाराना .त्थों पर रोष व्यक्त करते हुए मृतक के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग की। जिलाध्यक्ष सम्राट दीपक मौर्य ने कहा कि पुलिस ने जानबूझकर कर मुकदमे में धारदार हथियार का जिक्र नहीं किया। इससे साबित होता है कि पुलिस की अपराधियों से गहरी साठगांठ है। सम्राट अशोक सेवा संस्थान के जिला प्रभारी ने कहा कि जिस तरह आरोपियों ने अपने घर के सामने घेर कर धनराज पर हमला किया उससे यह साबित होता है कि आरोपी पूरी तरह तैयारी कर चुके थे। पुलिस ने आरोपियों को आनन फानन में जेल भेज कर उन्हें संरक्षण दिया जबकि उनका रिमांड लेकर उस धारदार हथियार की बरामदगी कराई जानी चाहिए। सम्यक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष .ष्ण कुमार मौर्य ने कहा कि फरार अभियुक्त को बुधवार को नाटकीय रूप से गिरतार कर लिया और उसे भी जेल भेज दिया जबकि उसका सीधे एनकाउंटर किया जाना चाहिए। प्रगतिशील विश्व पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय मौर्य ने पूरे घटनाक्रम को प्रदेश नेतृत्व के संज्ञान में लाने की बात कहते हुए आरोपियों द्वारा अर्जित संपत्ति के स्रोत की जांच कराने और आरोपियों के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान आनंद मौर्य, सियाराम मौर्य समेत दर्जनों कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे।



विश्व साइकिल दिवस पर सिद्धार्थनगर में स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण का संदेश, भव्य साइकिल रैली का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर सिद्धार्थनगर साइकिलिंग एसोसिएशन द्वारा जनपद में एक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का उद्देश्य आमजन को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने, पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने तथा युवाओं में खेल भावना को प्रोत्साहित करना था। रैली को नगर

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत प्रभावित परिवारों को मिली बड़ी राहत

दैनिक बुद्ध का संदेश



डुमरियागंज / सिद्धार्थनगर। मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के अंतर्गत बुधवार को तहसील सभागार डुमरियागंज में आयोजित कार्यक्रम में दुर्घटना से प्रभावित किसान परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की गई। इस दौरान पांच लाभार्थी परिवारों को पांच-पांच लाख रुपये का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपजिलाधिकारी विवेकानन्द मिश्रा ने की। मुख्य अतिथि पूर्व विधायक राघवेन्द्र प्रताप सिंह ने लाभार्थियों को सहायता राशि के चेक सौंपते हुए कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और उनके परिवारों की सुरक्षा एवं सम्मान के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि किसी दुर्घटना या अप्रत्याशित घटना के बाद प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। उपजिलाधिकारी विवेकानन्द मिश्रा ने योजना की जानकारी देते हुए बताया कि किसान की मृत्यु अथवा पूर्ण शारीरिक अक्षमता की स्थिति में

स्थायी लोक अदालत के लिए दो सदस्यों की होगी नियुक्ति, 2 जुलाई तक मांगे गए आवेदन

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। उ.प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशों के क्रम में जनपद सिद्धार्थनगर में गठित होने वाली स्थायी लोक अदालत के लिए दो सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस संबंध में पात्र एवं अनुभवी व्यक्तियों से 02 जुलाई 2026 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने बताया कि विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 22 बी (2)(ख)

पडरौना – कठकुईया मार्ग स्थित सिधुवा बाजार गड्डों में तब्दील, जनप्रतिनिधि व सम्बन्धित विभाग बना उदासीन

कुशीनगर। प्रदेश सरकार सड़क निर्माण के मद में जिले में हर वर्ष भारी भरकम धनराशि खर्च कर रही है। पुरानी सड़कों की मरम्मत के साथ नई सड़कों भी बनाई जा रही हैं, लेकिन पडरौना कठकुईया मेन रोड स्थित सिधुआ बाजार में किसी की नजर नहीं पड़ रही। यह सड़क पूरी तरह बिदहाल होने चुकी है। मार्ग बदहाल होने की वजह से इस रोड से होकर आने जाने राहगीरों को मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। इससे प्रतिदिन राहगीरों को गड्डे में गिरने की समस्या उत्पन्न हो रही है। पडरौना-कठकुईया मेन मार्ग से होकर गोडरिया तक का निर्माण करीब एक वर्ष पूर्व हुआ था। इसके बाद से इसकी कमी मरम्मत नहीं हुई। करीब डेढ़ किमी लंबी इस सड़क में खिरिया टोला, मोहन पट्टी, सिधुआ बाजार के सामने बड़े-बड़े गड्डे बने हुए हैं। इस रोड के अगल-बगल तो सड़क चलने लायक नहीं है। यहां वाहन



श्रीवास्तव, की उपस्थिति में कार्यक्रम का संचालन योग प्रमुख योगाचार्य महेश कुमार ने किया। रैली के दौरान प्रतिभागियों ने नियमित साइकिल चलाने, प्रदूषण कम करने तथा फिट एवं सक्रिय जीवनशैली अपनाने का संदेश दिया। रैली के समापन में प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को संगठन के पदाधिकारियों द्वारा मेडल प्रदान

तुलसियापुर हादसे पर सपा नेता मणेन्द्र मिश्रा ने जताया दुःख, 20 लाख मुआवजे की मांग

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। शोहरतगढ़ तहसील के तुलसियापुर चौराहे पर निर्माणाधीन स्वागत द्वार गिरने से एक व्यक्ति की मौत और चार लोगों के घायल होने की घटना पर समाजवादी पार्टी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मणेन्द्र मिश्रा ने गहरा दुःख व्यक्त किया है। उन्होंने जिलाधिकारी से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की मांग की है। मणेन्द्र मिश्रा ने कहा कि भारत सरकार के

मत्स्य पालन विभाग द्वारा संचालित प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत पंगेशियस क्लस्टर योजना में सिद्धार्थनगर अधिसूचित जनपद है। इसी योजना के तहत मंडी समिति से ग्राम पंचायत मदरहिया के पास मछली मंडी एवं व्यावसायिक मार्केट का निर्माण कराया जा

रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि निर्माण कार्य में मानकों की अनदेखी की गई, जिसके चलते कई महीनों से निर्माण कार्य में

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। खेसरहा विकास खंड के अंतर्गत स्थित बेलौहा चौराहे पर पिछले लगभग एक वर्ष से स्थायी सफाईकर्म की तैनाती न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना का लाभ क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है और साफ़ी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई

सीओ की अगुवाई में मुहर्रम से पहले सड़कों पर उतरी शोहरतगढ़ पुलिस

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़ / सिद्धार्थनगर। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी (सीओ) शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ कस्बे के विभिन्न ताजिया एवं जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम शोहरतगढ़ थाने से निकलकर तिरंगा तिराहा, मुख्य मार्ग, पुलिस पिकेट, शहीद बुई स्मारक मार्ग (रमजान गली), मस्जिद गली,



डीएम ने बी-पैक्स जोगिया का किया निरीक्षण, किसानों से की बातचीत

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। जिलाधिकारी शिवशरणप्पा जी.एन. ने बुधवार को विकास खंड जोगिया स्थित बी-पैक्स जोगिया का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने किसानों को वितरित किए जा रहे खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था की जानकारी ली। जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद किसानों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण के समय किसानों को 266.50 रुपये प्रति बोरी यूरिया तथा 1350 रुपये प्रति बोरी डीएपी उपलब्ध कराई जा रही थी। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों से खसरा-खतौनी का सत्यापन करने के बाद ही खाद का वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि खाद वितरण की पूरी प्रक्रिया शासन के निर्धारित नियमों के अनुरूप और पारदर्शी तरीके से सुनिश्चित की जाए।

स्थायी लोक अदालत में सदस्य पदों के लिए आवेदन आमंत्रित

दैनिक बुद्ध का संदेश

सिद्धार्थनगर। स्थायी लोक अदालत, जनपद सिद्धार्थनगर में सदस्य के दो रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इच्छुक एवं पात्र अभ्यर्थी निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत कर सकते हैं। प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अनुसार आवेदक को जनोपयोगी सेवाओं के क्षेत्र में पर्याप्त अनुभव होना आवश्यक है। इनमें वायु, सड़क एवं जलमार्ग परिवहन सेवाएं, डाक, तार एवं दूरभाष सेवाएं, विद्युत, प्रकाश एवं जल आपूर्ति, सार्वजनिक स्वच्छता एवं सफाई व्यवस्था, अस्पताल एवं औषधालय सेवाएं तथा बीमा सेवाएं शामिल हैं। चयनित सदस्यों को प्रति बैठक 2,000 रुपये बैठक शुल्क तथा 5,000 रुपये प्रतिमाह यात्रा भत्ता प्रदान किया जाएगा। नियुक्ति की अवधि पांच वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु पूर्ण होने तक, जो भी पहले हो, निर्धारित की गई है। आवेदन पत्र के साथ दो नवीनतम पासपोर्ट आकार के फोटो तथा दो स्व-पता लिखित एवं डाक टिकट लगे लिफाफे संलग्न करना अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपना आवेदन अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल न्यायालय, सिद्धार्थनगर के नाम संबोधित कर 02 जुलाई 2026 तक कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा कराना होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी प्रभारी सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिविल न्यायालय, सिद्धार्थनगर द्वारा उपलब्ध कराई गई है।

डीएम के आश्वासन के बाद भी नहीं हुई तैनाती, बेलौहा एक साल से सफाईकर्मों विहीन

दैनिक बुद्ध का संदेश



सिद्धार्थनगर। खेसरहा विकास खंड के अंतर्गत स्थित बेलौहा चौराहे पर पिछले लगभग एक वर्ष से स्थायी सफाईकर्म की तैनाती न होने से स्थानीय लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि शासन की महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत मिशन योजना का लाभ क्षेत्र को नहीं मिल पा रहा है और साफ़ी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई

सीओ की अगुवाई में मुहर्रम से पहले सड़कों पर उतरी शोहरतगढ़ पुलिस

दैनिक बुद्ध का संदेश

शोहरतगढ़ / सिद्धार्थनगर। आगामी मुहर्रम पर्व को शांतिपूर्ण एवं सकुशल संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में क्षेत्राधिकारी (सीओ) शोहरतगढ़ मयंक द्विवेदी और प्रभारी निरीक्षक नवीन कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ कस्बे के विभिन्न ताजिया एवं जुलूस मार्गों का निरीक्षण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान पुलिस टीम शोहरतगढ़ थाने से निकलकर तिरंगा तिराहा, मुख्य मार्ग, पुलिस पिकेट, शहीद बुई स्मारक मार्ग (रमजान गली), मस्जिद गली,



सम्पादकीय

वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये
चलाये जा रहे पुनर्वास
कार्यक्रमों में शिथिलता
अपनायी जाती है तो सरस्वी से
हासिल होने वाली उपलब्धियां
व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है
कि नशा एक ऐसा रोग है,
जिसका कोई आसान इलाज
उपलब्ध नहीं है। जहां एक
ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति
पर अंकुश लगाना जरूरी है,
तो दूसरी ओर इसकी तलब
को काबू करने के लिये भी
प्रयास जरूरी हैं...

निस्संदेह, नशे का निरंतर फैलाता काला कारोबार एक राष्ट्रीय संकट है। देश के विभिन्न भागों में करोड़ों-अरबों रुपये मूल्य के विदेशों से आने वाले नशीले पदार्थों की बरामदगी भयावह संकट की तसवीर उकेरती है। संगठित विदेशी अपराधियों की साजिशों और देश में फैले नशा तस्करों का गड़जोड़, इस नशीले जहर के कारोबार को चला रहा है। आज जरूरत इस बात की है कि देश की तमाम खुफिया एजेंसियां व राज्य के विशेष पुलिस बल योजनाबद्ध ढंग से नशा कारोबारियों की कमर तोड़ें। लेकिन फिर भी कई राज्यों द्वारा चलाये जा रहे नशा विरोधी अभियान बिगड़ते हालात सुधारने में किसी हद तक मददगार साबित हो सकते हैं। पिछले दिनों पंजाब में भी ऐसा अभियान चलाया गया। अब सीमावर्ती जम्मू-कश्मीर में वहाँ से गहराते नशे के संकट के खिलाफ अभियान शुरू किया जा रहा है। सवाल यह है कि राज्य में नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई शुरू करने में इतना वक्त क्यों लगा? अब भले ही देर से ही सही, यह पहल शुरू करना वक्त की जरूरत है। नशे के नश्टर से हमारी युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है और कई घरों के चिराग असमय बुझ रहे हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, बीस जिलों का दौरा करके सी वीदसीय नशा मुक्त जम्मू-कश्मीर मार्च का नेतृत्व कर रहे हैं। वहीं इस अभियान का सुखद पहलु यह है कि दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में, इस कोशिश को प्रतिबंधित संगठन जमाते—ए-इस्लामी के एक गुट का भी समर्थन मिला है। कहना कठिन है कि इस समर्थन का हकीकत में असर कितना होगा। लेकिन इस घोषणा ने सकारात्मक संदेश जरूर दिया है कि समाज के विभिन्न वर्गों के सामूहिक प्रयासों से ही इस भयावह होते संकट का मुकाबला किया जा सकता है। सी मायने में समाज में व्याप्त तमाम वैचारिक मतभेदों को दरकिनार करते हुए, सामूहिक व निरंतर प्रयासों से ही नशा मुक्ति की लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाया जा सकता है। वास्तव में नशा विरोधी अभियान के मार्ग में बाधा पैदा करने वाली जटिलताओं के मुकाबले के लिये

कुछ दिन, कुछ माह के अभियान के बजाय साल में 365 दिन चलने वाली रणनीति अपनाने की जरूरत है। कभी-कभार चलाए जाने वाले अभियान इसके लक्ष्य को पाने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हो सकते। इस संकट के समाधान के लिये नशे की लत के सामाजिक पहलुओं की भी व्यापक पड़ताल जरूरी है। कारगर समाधान हेतु सामाजिक स्तर पर रणनीति बनाने की जरूरत होती है। निस्संदेह, नशे की लत के तमाम कारण हमारे समाज में विद्यमान हैं। जिनके निराकरण की दिशा में भी कदम उठाने की जरूरत है। मसलन इस व्यसन के मूल में समाज में व्याप्त बेरोजगारी, निराशा, सामाजिक व आर्थिक असमानताएं, बुरी संगत का असर तथा मादक पदार्थों की सजान में आसान उपलब्धता आदि कारक निहित हैं। चिंताजनक है कि नशा अब स्कूल-कालेजों तक को अपनी गिरफ्त में ले रहा है। कई राज्यों में नशे की आपूर्ति में बच्चों को इस्तेमाल करने के चिंताजनक उदाहरण सामने आए हैं। वहीं यदि नशा मुक्ति के लिये चलाये जा रहे पुनर्वास कार्यक्रमों में शिथिलता अपनायी जाती है तो सख्ती से हासिल होने वाली उपलब्धियाँ व्यर्थ हो जाती हैं। यह सत्य है कि नशा एक ऐसा रोग है, जिसका कोई आसान इलाज उपलब्ध नहीं है। जहां एक ओर नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर अंकुश लगाना जरूरी है, तो दूसरी ओर इसकी तलब को काबू करने के लिये भी प्रयास जरूरी है। दुर्भाग्यपूर्ण है कि नशे की डोज जुटाने के लिये कुछ छात्र व युवा अपराध की राहों में फिसल जाते हैं। इसलिये जरूरी हो जाता है कि नियमित रूप से नशा तस्करों और ड्रग पेडलरों की गिरफ्तारी करके तुर्त नशे जा दी जाए। वहीं दूसरी ओर नशे की खरीद-फरोख्त में संलिप्तता पर ड्राइविंग लाइसेंस रद्द करने, पासपोर्ट निस्स करने से भी जहरीले कारोबार पर अंकुश लगाने में मदद मिल सकती है। साथ ही सीमावर्ती संवेदनशील राज्यों में, जहां सीमा पार से नशे की तस्करी आतंकवाद को जन्म देने के लिये की जा रही है, वहां अतिरिक्त सावधानी की भी जरूरत है। नशा तस्करों की गिरफ्तारी के तुर्त बाद सजा देना, इस अभियान में मददगार साबित होगा।

जिनके इलाज से टिके मर्ज, निकले मरीज

गांवों की अपनी मजबूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद डाक्टर शहरों में टिके रहना चाहते हैं और गांवों में झोलाछाप डॉक्टरों की चल निकलती है। कहते हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। अगर वही फर्जी निकल जाए, तब तो भगवान ही मालिक है। तब तबीयत में सुधार के लिए भगवान को भेजी गई अर्जी भी काम नहीं आती। मर्ज रह जाता है, मरीज निकल लेता है। उम्रकराज जनकलाल अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं। नियमित जांचें कराते हैं। एक दिन इसी मंशा से किसी संजीवनी क्लीनिक पर पहुंचे। लंबी प्रतीक्षा के बाद एक डॉक्टर प्रकट हुआ। उसने उन पर एक नजर डाली और सीधे पर्ची पर उतर आया। ताबड़तोड़ कलम घसीटते हुए बोला, 'आप तो बिल्कुल ठीक हैं, बस अंडरवेट हैं। सुबह की ताजी हवा खाएं और ये दवाएं लीजिए। थोड़ी महंगी हैं। ठीक हो जाएंगे।' जनकलाल ने अपने बच्चे-खुबे दांतों तले अंगुली दबा ली, डॉक्टर तो पहुंचा हुआ मालूम पड़ता है। बिना जांचे पार्श्व लिख दिया? जनकलाल खुद ही अपनी नब्ब टटोलते हुए विचारने लगे— मैं तो जिंदगीभर से ऐसे ही हूँ, दुबला-पतला! फिर उन्होंने डॉक्टर को देखा। वह मुंह में जर्दा दाबे सीकिया पहलवान लगता था! वे बोले, 'आप भी तो अंडरवेट हैं डॉक्टर साब!' डॉक्टर मुख ऊपर करके हंसा, वरना पीक बाहर आ जाती। फिर ठसके से पूछा, 'डॉक्टर मैं हूँ या आप?' जनकलाल सकपका गए, 'जी, आप। मैंने तो ऐसे ही पूछ लिया।' जनकलाल के जवाब से डॉक्टर को भरोसा आया कि वही डॉक्टर है, सो हो... हो... कर हंसा, 'वो क्या है कि मेरी तबीयत जरा खराब है?' यह मामला हास्यास्पद—सा लगता है, लेकिन संजीवनी क्लीनिकों में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे डॉक्टरों के मामले को देखते हुए सच जान पड़ता है। झोलाछाप डॉक्टरों के बारे में कौन नहीं जानता। पर कौन जानता था कि फर्जी डिट्ठी धारक, झोलाछाप डॉक्टरों की भांति क्लीनिकों में बैठकर मरीजों की जान से खेलने लगेंगे। गांवों में आज भी झोलाछाप डॉक्टर पाए जाते हैं। एक गांव में रोजमर्रा की खरीददारी के लिए भरने वाले साप्ताहिक बाजार के दिन, एक इंजेक्शन वाला झोलाछाप डॉक्टर काफी चर्चा में रहा। वह बीच बाजार, गांव की सड़क के किनारे पुलिया की सुरक्षा दीवार के शीर्ष चबूतरे पर मरीज को लिटाता और बिना किसी इज्ञात मरीज के कपड़ों के ऊपर से ही इंजेक्शन टूंस कर इलाज करता था! मरीज अपने नितंब दबाए फीस चुकाते और निकल लेते थे। बहरहाल, गांवों की अपनी मजबूरी है। तमाम कोशिशों के बावजूद डाक्टर शहरों में टिके रहना चाहते हैं और गांवों में झोलाछाप डॉक्टरों की चल निकलती है। क्लीनिकों के हालिया फर्जीवाड़ा के चलते झोलाछाप कॉकरोच शहरों में भी सुरसुराने लगे हैं?

टूटे समाजों में भरोसा लौटाने के लिए सम्मान

उन्होंने दिखाया कि शांति मिशन केवल सीमाओं की निगरानी नहीं, बल्कि टूटे हुए समाज में भरोसा लौटाने की जिम्मेदारी भी है। यही कारण है कि संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें 'जेंडर एडवोकेट' यानी लैंगिक समानता की पैरोकार के रूप में सम्मानित करने का निर्णय लिया। आज जब युवा पीढ़ी त्वरित सफलता और सोशल मीडिया की चमक से प्रभावित है, तब मेजर अभिलाषा बराक जैसी शख्सियतें यह याद दिलाती हैं कि...

अभिलाषा की कहानी केवल एक सैन्य अधिकारी की कहानी नहीं, बल्कि उस नए भारत की कहानी है जहां बेटीयां सीमाएं नहीं संभावनाएं देखती हैं। जहां वर्दी केवल ताकत का प्रतीक नहीं, बल्कि संवेदनशील नेतृत्व और मानवीय मूल्यों का चेहरा भी बन रही है। दुनिया में सैनिकों की पहचान अक्सर युद्ध और सीमाओं से जुड़ी होती है। लेकिन कुछ सैनिक ऐसे भी होते हैं जो वर्दी पहनकर केवल सुखशाही ही नहीं देते, बल्कि भरोसा, संवेदनशीलता और उम्मीद भी बांटते हैं। भारतीय सेना में मेजर अभिलाषा बराक आज ऐसी ही पहचान बन चुकी हैं। संयुक्त राष्ट्र ने उन्हें वर्ष 2025 के प्रतिष्ठित 'यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवॉर्ड' के लिए चुना है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के दौरान महिलाओं और क्राशोरियों के बीच विश्वास निर्माण, संवाद और संवेदनशील नेतृत्व के लिए न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। यह उपलब्धि सिर्फ एक सैन्य अधिकारी की सफलता नहीं है। यह उस भारतीय की कहानी है, जहां बेटीयां अब केवल सपने नहीं देख रही, बल्कि दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित मंचों पर देश का प्रतिनिधित्व भी कर रही हैं। अभिलाषा बराक का संबंध हरियाणा के रोहतक से है। उनका बचपन सेना व अनुशासन और देशभक्ति के माहौल में बीता। उनको पिता कर्नल एस. ओम सिंह भारती सेना में रहे हैं। परिवार की सैन्य परंपरा

अमिलाषा के व्यक्तित्व को प्रभावित किया। तभी उनके भीतर देशसेवा केवल एक पेशा नहीं, बल्कि जीवन का लक्ष्य बनती चली गई।



हालांकि उनका जन्म तमिलनाडु के वेंलिंगटन स्थित सैन्य अस्पताल में हुआ, लेकिन परिवार की जड़ें रोहतक से जुड़ी रहीं। अभिलाषा ने जब भारतीय सेना की पहली महिला कॉन्बैट एविएटर बनकर इतिहास रचा, तब हरियाणा ने उन्हें गर्व के साथ 'रोहतक की बेटी' कहा। उन्होंने दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की और बाद में चेन्नई की ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी से सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त किया। साल 2022 भारतीय सेना के इतिहास में एक अहम मोड़ आया, जब अभिलाषा भारतीय सेना की पहली महिला कॉन्बैट एविएटर बनीं। यह भारतीय सेना के बदलते स्वरूप का प्रतीक भी थी। लंबे समय तक सेना के लड़ाकू और

एविगेशन विंग को पुरुष प्रधान क्षेत्र माना जाता रहा। महिलाओं की भूमिका सीमित समझी जाती थी। उन्होंने यह साबित किया कि साहस, नेतृत्व और क्षमता का कोई भी लिंग नहीं होता। उनकी इस उपलब्धि ने देशभर की हजारों लड़कियों को यह संदेश दिया कि अब भारतीय सेना में महिलाओं के लिए 'सीलिंग' नहीं बची है। आज संयुक्त राष्ट्र के शांति मिशन केवल सैन्य कार्यवाही के तक सीमित नहीं है। उनका उद्देश्य संघर्ष प्रभावित समाज में भरोसा बहाल करना भी है। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र

अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) के तहत तैनात भारतीय बटालियन में अमिलाषा बराक महिला सहभागिता दल की कमांडर के रूप में कार्यरत हैं। युद्ध प्रभावित इलाकों में महिलाएं और बच्चियां सबसे ज्यादा असुरक्षित होती हैं। सुरक्षा क्षेत्रों में महिला सैनिकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि वे स्थानीयवासियों महिलाओं से ज्यादा सहज संवाद स्थापित कर पाती हैं। अमिलाषा बराक ने लेबनान में महिलाओं और किशोरियों के साथ संपर्क कार्यक्रम चलाए, सामुदायिक गतिविधियों में हिस्सा लिया और शांति सैनिकों को लैंगिक संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी दिया। उन्होंने वेद दिखाया कि एक सैनिक केवल सुरक्षा का प्रतीक नहीं,

बलिک सामाजिक विश्वास का चेहरा भी हो सकता है। संयुक्त राष्ट्र ने उनके इसी मानवीय नेतृत्व और संवेदनशील कार्यशैली को सम्मानित करने का फैसला किया। मेजर अभिलाषा बराक इस प्रतिष्ठित सम्मान को पाने वाली भारत की तीसरी महिला अधिकारी हैं। उनसे पहले सुमन गुवानी और राधिका सेन भी संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों में अपने उल्लेखनीय कार्यों के लिए सम्मानित हो चुकी हैं। मेजर सुमन गवानी को दक्षिण सूडान में महिलाओं और अधिकारों और सामुदायिक भागीदारी को मजबूत करने के लिए सम्मान मिला था। वहीं मेजर राधिका सेन ने संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में महिला सुरक्षा और सामाजिक भरोसा कायम करने की दिशा में अहम कार्य किया। अब अभिलाषा बराक का इस सूची में शामिल होना भारतीय महिला सैन्य नेतृत्व की निरंतर बढ़ती वैश्विक स्वीकार्यता का प्रमाण है। एक समय था जब हरियाणा को बेटियों के प्रति रूढ़ सोच वाले राज्य के रूप में देखा जाता था। लेकिन आज वही हरियाणा खेल, सेना, विज्ञान और प्रशासन में देश को नई पहचान देने वाली बेटियाँ दे रहा है। अभिलाषा बराक इसी बदलाव का सबसे मजबूत चेहरा हैं। उनकी उपलब्धि यह भी दिखाती है कि यदि अवसर, शिक्षा और विश्वास मिले तो भारतीय महिलाएं किसी भी क्षेत्र में विश्व स्तर पर नेतृत्व कर सकती हैं। अभिलाषा बराक की सबसे बड़ी ताकत यही है कि उन्होंने सैनिक की कठोर छवि के भीतर मानवीय संवेदना को जीवित रखा।

दूसरा, नेपाल और भारत के बीच उभरपक्षीय मामले में ब्रिटेन को शामिल करने की इच्छा भी गलत है। भारत ने बार-बार कहा है कि वह बाउंडरी बातचीत में किसी तीसरे पक्ष को कभी नहीं कबूल करेगा, चाहे वह पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश या नेपाल के साथ हो।' जो भी हो, बालेन्द्र शाह का यह बयान भारत-नेपाल संबंधों का कड़वा सच है, जिसे वहां के तथाकथित राष्ट्रवादी नेता और प्रतिक्रियावादी पचा नहीं

अब तक नेपाल के किसी भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी कब्जा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन-किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है। गत 27 मार्च को पद संभालने के बाद से प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने एक बार भी संघीय संसद को संबोधित नहीं किया थाकृयहां तक कि अनिवार्य साप्ताहिक प्रश्न-उत्तर सत्रों के दौरान भी नहीं। उनकी चुप्पी तोड़ने और विधायिका के प्रति जवाबदेही दिखाने का दबाव उन पर लगातार बढ़ रहा था। और फिर रविवार को जब बालेन्द्र शाह संसद में बोले, सभी सन्याटे में आ चुके थे। उन्होंने अपने आलोचकों को शांत करने के बजाय, मानो डंक मारने वाली मधुमक्खियों का एक झुंड ही छोड़ दिया। जिसे अंग्रेजी में 'पैंडोरा बॉक्स खोलना' कहते हैं। संसद में दो अलग-अलग सवालों का जवाब देते हुए, शाह ने सबसे पहले कहा कि कालापानी, लिमियापुरा और लिपुलेख विवाद को सुलझाने के लिए भारत के साथ प्रयास जारी हैं। लेकिन, फिर उन्होंने यह भी जोड़ा कि न

केवल भारत ने नेपाली क्षेत्रों पर अतिक्रमण किया है, बल्कि नेपाल ने भी कई जगहों पर भारत की जमीन पर अतिक्रमण किया है। उन्होंने यह भी कहा कि चूंकि भारत के साथ मौजूदा सीमा विवादों में से कई की जड़ें 1816 में ब्रिटिश भारत के साथ हुई सुगौली संधि में हैं, इसलिए उनकी सरकार भारत-नेपाल सीमा चर्चाओं में ब्रिटिश पक्ष को शामिल करने की कोशिश कर रही है। काठमांडू पोस्ट जैसा अखबार भी इस बयान से हैरान था। अगले दिन के सम्पादकीय में अखबार लिखता हैकू 'सीमा विशेषज्ञों के साथ-साथ उन वरिष्ठ पूर्व सरकारी अधिकारियों के अनुसार, जिन्होंने अपने भारतीय समकक्षों के साथ बातचीत की है, ऐसा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, जिसमें भारत ने कभी 'नेपाली अतिक्रमण' का मुद्दा उठाया हो। इसलिए, प्रधानमंत्री का यह बयान



निविष्णु की सीमा वार्ता में भारत के पक्ष को मजबूत करता है।' कोई राष्ट्रीय अखबार तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करे, तो यह उभयपक्षीय हितों के लिए अच्छा नहीं है। भारत से यदि भूमि विवाद नहीं होता, तो 'बाउंडरी वर्किंग ग्रुप' का गठन क्यों किया गया? संयुक्त तकनीकी समिति ने लगभग 26 वर्षों तक कार्य किया। यह दावा किया गया कि सीमा संबंधी 97 प्रतिशत समस्याओं का समाधान कर लिया गया। शेष तीन प्रतिशत का समाधान करना उनकी क्षमता से

भारतीय भूमि अतिक्रमण मुद्दे पर घिरे बालेन्द्र

मुद्दे पर घिरे बालेन्द्र

पर था। उसमें कालापानी-लिम्पियाधरा शामिल है। कुल 370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल के साथ सबसे बड़ा अतिक्रमण है। इसके अलावा 24 किलोमीटर का सुस्ता क्षेत्र और लगभग 15 किलोमीटर क्षेत्रफल वाले अन्य स्थान भी इसमें हैं। कुल मिलाकर, ऐसे लगभग 7 स्थान हैं जो 606 वर्ग किलोमीटर का कुल क्षेत्रफल घेरते हैं। इस स्थिति के बने रहने के पीछे सबसे महत्वपूर्ण कारणों में एक, सीमांकन के लिए पुराने मानचित्रों और दस्तावेजों की अनुपलब्धता है। काश! काठमांडू पोस्ट ने बुद्धि नारायण श्रेष्ठ की पुस्तक 'द नेचुरल एनवायरनमेंट्स एंड द शिपिंग बॉर्डर्स ऑफ नेपाल' में बर्नाडो माइकल द्वारा की गई टिप्पणी पर गौर किया होता, 'आज भी, भारत और नेपाल के बीच सीमा विवादों की उपस्थिति यह स्पष्ट रूप से दर्शाती है कि आधुनिक सीमाओं के निर्धारण की यह परियोजना सदैव एक 'अधूरी परियोजना' ही बनी रहेगी।' नेपाल के लिए मुश्किल यह है कि लिपुलेख के मुद्दे पर चीन उसके साथ नहीं खड़ा है। लिपुलेख-लिम्पियाधरा ट्राइजंक्शन भारत का है, उसकी पुष्टि 15 मई, 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चीन की राजकीय यात्रा के दौरान हुआ व्यापार समझौता है। यह भारत और चीन के बीच एक द्विपक्षीय समझौता था, जिस पर चीनी प्रधानमंत्री ली कडियांग के साथ पीएम मोदी ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें औपचारिक रूप से लिपुलेख दर्रे के माध्यम से सीमा व्यापार

पर सहमति बनी थी। 41—सूत्री संयुक्त बयान के बिंदु 28 में लिपुलेख दर (कियांगला) को औपचारिक रूप से एक द्विपक्षीय सीमा व्यापार और तीर्थयात्रा मार्ग के रूप में मान्यता दी गई थी। तब नेपाली कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला ने कड़ा विरोध जताते हुए कहा, कि भारत और चीन ने उसकी सहमति के बिना, उसके दावे वाले क्षेत्र से होकर व्यापार करने पर बातचीत की है। बाद के दिनों में नेपाल के तीन प्रधानमंत्रियों (केपी शर्मा ओली, प्रचंड और शेर बहादुर देउबा ने लिपुलेख—लिम्पियाधुरा के बॉल को जमकर खेला। बालेन्द्र शाह से पहले पीएम ओली इस मुद्दे को उठाने 3 सितम्बर, 2025 को पेइचिंग में आहूत शिपेनमान चौक विजय दिवस समारोह तक गए लेकिन, चीनी सत्ता प्रतिष्ठान ने उसे अनसुना कर दिया। चीन और भारत तय कर चुके थे कि लिपुलेख—लिम्पियाधुरा द्राइजंक्शन के बरास्ते जून, 2026 में उभयपक्षीय व्यापार होना है। बहरहाल, प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह ने बर्बर के छले में हाथ डाल दिया है। अब तक नेपाल के किसी

भी प्रधानमंत्री ने ऐसा बयान संसद में नहीं दिया था कि भारतीय भूमि को उनके देश ने भी कब्जा कर रखा है। बालेन्द्र शाह को अब बताना है, कि नेपाल ने किन—किन जगहों पर भारतीय भूमि का हरण किया है। कोई संसद यह चाह रहे हैं कि संसद के रिकार्डों से यह बयान स्पष्ट किया जाये। लेकिन, जुबान से निकली बात और कमान से छूटने की वापसी नहीं हो सकती। नेपाली मीडिया भी हतप्रभ है। नेपाली अखबार काठमांडू पोस्ट प्रधानमंत्री शाह के बयान को अपरिपक्व मानते हुए लिखता है, 'अगर उन्होंने 'अतिक्रमण' शब्द के बजाय 'सीमा-पार के कब्जे' शब्द का इस्तेमाल किया होता, तो कोई विवाद नहीं होता।

सिद्धार्थनगर का सबसे बड़ा प्रिन्टींग पब्लिकेशन हाउस... **मिनी सी.एस.डी. के लिए अभी काटें आर्डर**

बुद्ध पब्लिकेशन

ऑफसेट एण्ड प्रिन्टर्स

* सी.एस.टी. बिजुल/फार्म * कार्यालय रजिस्टर * स्कूल फार्म/फार्म/डायरी * फायरफोर्ट
 * कलर पोस्टर * कलर डिप्लिमा फार्म * डेक्कन होटल पैड * बैंक फार्म
 * निकट-हीरो एजेंसी * ग्रीनम न्यूकरपूर-सिद्धार्थनगर (उ.प्र.)

☎ 8795951917, 9453824459

E-mail: info@buddhapublications.com
 Web: www.buddhapublications.com
 E-Mail ID: buddhaanandashivnagar@gmail.com

पैरावेट कार्यकर्ताओ ने बकाया भुगतान को लेकर जिलाधिकारी से लगाई गुहार

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। जनपद के पैरावेट कार्यकर्ताओ ने पशुगणना, पांचवें चरण के टीकाकरण, एआईपीडी कैल्विन एवं विभिन्न विभागीय कार्यों के भुगतान में हो रही देरी को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए शीघ्र भुगतान कराए जाने की मांग की है। कार्यकर्ताओ ने आरोप लगाया कि लंबे समय से कार्य करने के बावजूद उन्हें उनकी प्रोत्साहन राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिससे उनमें भारी निराशा और आक्रोश व्याप्त है। जिलाधिकारी को संबोधित पत्र में पैरावेट कार्यकर्ताओ ने बताया कि वे विभाग के लिए पशुगणना, पांचवां टीकाकरण अभियान, एआईपीडी कैल्विन संचालन सहित कई महत्वपूर्ण कार्यों का निष्पादन करते हैं। इसके बावजूद उन्हें समय से भुगतान नहीं मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पैरावेट कार्यकर्ताओ को विभाग से कोई नियमित वेतन



मांग को लेकर कार्यकर्ता लगातार प्रयास कर रहे हैं। इस संबंध में वे कई बार मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी सीबीओ से मिले तथा लिखित रूप से ज्ञापन भी सौंपे। कार्यकर्ताओ का कहना है कि हर बार उन्हें आश्वासन तो दिया गया, लेकिन

भुगतान की दिशा में कोई ठोस कार्यवाई नहीं हुई। पैरावेट कार्यकर्ताओ के अनुसार 6 मार्च को भी सीडीओ को ज्ञापन सौंपा गया था। उस समय उन्हें आश्वासन दिया गया कि 31

सेवा, समर्पण के रूप में मनाया जायेगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिन- अखिलेश सिंह

तीन दिवसीय कार्यक्रम में रक्तदान शिविर, हिन्दू सम्मेलन, सहभोज का आयोजन

दैनिक बुद्ध का संदेश

बस्ती। विश्व हिन्दू महासंघ द्वारा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म दिन सेवा और समर्पण के रूप में मनाया जायेगा। जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने पत्रकारों से बातचीत में बताया कि इस अवसर पर तीन दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन हरैया तहसील क्षेत्र में स्थित तपसीधाम में किया गया है। 5 जून को विशाल रक्तदान शिविर एवं बाबा भोलेनाथ का दिव्य रुद्राभिषेक होगा। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डीआईजी संजीव त्यागी को मुख्य अतिथि और विशिष्ट अतिथि के रूप में पुलिस अधीक्षक डा. यशवीर सिंह आमंत्रित किया गया है। बताया कि 6 जून को अखण्ड रामायण का पाठ शुरु होगा और 7 जून को विशाल



मुख्य अतिथि प्रकाश सिंह प्रमुख सचिव और विशिष्ट अतिथि के रूप में डा. मंगलेश कुमार श्रीवास्तव महापौर गोरखपुर, राजमाता राजमहल बस्ती आशिमा सिंह हिस्सा लेंगी। गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट कर लौटे विश्व हिन्दू महासंघ जिलाध्यक्ष अखिलेश सिंह ने

कहा कि उन्होंने तीन दिवसीय कार्यक्रमों के रूप की विस्तार से जानकारी दिया। कहा कि रक्तदान के द्वारा हम दूसरे की जान बचाने का माध्यम बनते हैं। पूरा प्रयास है कि लगभग 500 यूनिट रक्तदान कराया जाय। बताया कि तीन दिवसीय कार्यक्रम को सम्पन्न कराने के लिये पदाधिकारियों में दायित्वों का वितरण कर दिया गया है और तपसी धाम

में महत्त्व जय बक्श दास के मार्गदर्शन में जोरों से तैयारियां चल रही है। अखिलेश सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में सर्व समाज के विकास के साथ ही हिन्दू अस्मिता को नयी पहचान दिया है। उनके जन्म दिन को सेवा और समर्पण के रूप में पूरी भव्यता और संकल्पों के साथ मनाया जायेगा।

काँकरोच जनता पार्टी की जांच संबंधी याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इन्कार

दैनिक बुद्ध का संदेश

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने शर्काँकरोच जनता पार्टीश और उसके संस्थापक अभिजीत दीपके की गतिविधियों की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) तथा प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से जांच कराने की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई करने से इन्कार कर दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता कर्नाटक के बेंगलुरु निवासी हैं और मामले का उत्तर प्रदेश से कोई प्रत्यक्ष व विशेष संबंध नहीं है, इसलिए उन्हें पहले कर्नाटक हाईकोर्ट का रुख करना चाहिए।



और राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रभावित करने वाली गतिविधियों में सलिप्त है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि यह एक सुनियोजित डिजिटल अभियान है, जिसका उद्देश्य युवाओं को प्रभावित करना, सार्वजनिक अव्यवस्था को बढ़ावा देना तथा केंद्र सरकार के प्रति असंतोष पैदा करना है। याचिका में यह भी कहा गया था कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, सिग्नल और एक्स सहित विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर संचालित खातों, पेजों, चैनलों और समूहों के माध्यम से कथित तौर पर राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चलाई जा रही हैं। इसी आधार पर याचिकाकर्ता ने शर्काँकरोच जनता पार्टीश से जुड़े सभी

सोशल मीडिया अकाउंट, पेज, चैनल, समूह और प्रोफाइल को स्थायी रूप से बंद करने और ब्लॉक करने की मांग भी की थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता स्वयं बेंगलुरु के निवासी हैं और उन्होंने राष्ट्रीय महत्व के विषय को उठाया है। ऐसे में उन्हें सबसे पहले कर्नाटक हाईकोर्ट जाना चाहिए था। अदालत ने स्पष्ट किया कि वर्तमान याचिका में उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई ऐसा विशेष तथ्य नहीं है, जिससे लखनऊ पीठ के अधिकार क्षेत्र का आधार बनता हो। अदालत ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता ने यह दलील दी कि उन्होंने कुछ



कुंआनों नदी बस्ती की जीवन रेखा: इसे स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी-नेहा वर्मा

दैनिक बुद्ध का संदेश



बस्ती। बुधवार को नदियों को स्वच्छ और अवरिल बनाये रखने की कड़ी में नगर पालिका अध्यक्ष नेहा वर्मा और वरिष्ठ भाजपा नेता अंकुर वर्मा द्वारा कुंआनो के अमहट घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। नेहा वर्मा ने कहा कि कुंआनो बस्ती की जीवन रेखा है। नदी प्रदूषण का शिकार है। नदियों को स्वच्छ रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। इस दिशा में नगर पालिका का चरणबद्ध प्रयास जारी रहेगा। कुंआनो नदी के स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेने के

बाद अध्यक्ष नेहा वर्मा ने श्रमदान कर रहे कर्मियों का उत्साहवर्धन किया और निर्देश दिए कि सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए। उन्होंने कहा कि नदियाँ हमारी संस्कृति और जीवन का आधार हैं। इन्हें स्वच्छ रखना केवल प्रशासन की नहीं, बल्कि हर एक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि अंकुर वर्मा ने कहा कि नदियों के अस्तित्व को बचाने और उन्हें प्रदूषण मुक्त



बनाने के संकल्प के साथ विशेष नदी सफाई अभियान युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है। कहा कि जन भागीदारी से नदियों को स्वच्छ करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाये जा रहे हैं। उन्होंने स्वच्छता अभियान में हिस्सा लेते हुये लोगों से आग्रह किया कि जीवन दायिनी नदियों को स्वच्छ रखने की दिशा में अपनी ओर से भी पहल करें। कहा कि सरकार और प्रशासन नदियों को साफ रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है, लेकिन यह

अभियान के दौरान पालिका के अवधेश यादव सफाई एवं खाद्य निरीक्षक अवधेश यादव, विक्रम चौहान, विवेक श्रीवास्तव, सूरज गुप्ता, अरुण पाण्डेय के साथ ही नगर पालिका के सभी सफाई नायक, बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी और स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे। सभी ने मिलकर इस स्वच्छता अभियान में अपना पूर्ण सहयोग देने और आम जनता को जागरूक करने का सामूहिक संकल्प लिया।

आईजीआरएस शिकायत पर फर्जी रिपोर्ट लगाने का आरोप, नाली सफाई की मांग

कुशीनगर। जनपद के तुर्कपट्टी थाना क्षेत्र के महुआ बुजुर्ग गांव में नाली सफाई और अतिक्रमण की समस्या को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश व्याप्त है। ग्रामीणों का आरोप है कि इस संबंध में 10 से अधिक बार आईजीआरएस पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है, लेकिन आज तक समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सका है। ग्रामीणों के अनुसार प्रत्येक बार संबंधित विभाग द्वारा शिकायत का निस्तारण दिखा

दिया जाता है। जबकि मौके पर स्थिति जस की तस बनी हुई है। क्षेत्र के मुख्य चौराहे पर स्थित नाली के ऊपर बड़े पैमाने पर अतिक्रमण किया गया है। कई दुकानदारों ने नाली के ऊपर सिलापट रखकर उसके ऊपर स्थायी रूप से प्लास्टर और अन्य निर्माण कार्य करा लिए हैं। जिससे नाली पूरी तरह ढंक गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कुछ दुकानदार आज भी अपना सिलापट हटाने को तैयार नहीं हैं। इसके कारण

नाली की पूर्ण सफाई नहीं हो पा रही है। सफाई कर्मियों और जेसीबी मशीन को नाली के अंदर तक पहुंचाने में कठिनाई होती है। जिससे केवल आंशिक सफाई ही संभव हो पाती है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि बार-बार शिकायतों के बावजूद संबंधित विभाग द्वारा केवल औपचारिकता निभाते हुए सीमित सफाई कर फोटो अपलोड कर शिकायतों का निस्तारण कर दिया जाता है। जबकि नाली के ऊपर

अतिक्रमण और गंदगी की मूल समस्या आज भी बरकरार है। नाली की नियमित और पूर्ण सफाई न होने से क्षेत्र में जलभराव, दुर्गंध और जल निकासी की गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई है। बरसात के मौसम में स्थिति और भी विकट होने की आशंका है। जिससे आसपास के दुकानदारों और राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। स्थानीय नागरिकों ने प्रशासन से मांग किया है कि मौके पर वास्तविक

स्थिति का निरीक्षण कराया जाए तथा नाली के ऊपर किए गए अतिक्रमण और सिलापट को हटवाकर नाली की पूर्ण सफाई सुनिश्चित की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि जनहित से जुड़े इस मुद्दे का शीघ्र समाधान आवश्यक है ताकि लोगों को गंदगी और जलभराव की समस्या से राहत मिल सके। ग्रामीणों ने जिला प्रशासन एवं संबंधित अधिकारियों से निष्पक्ष जांच कर प्रभावी कार्रवाई की मांग की है।

25 हजार संविदा कर्मियों की बहाली की मांग, संघर्ष समिति ने ऊर्जा मंत्री के निर्देश का किया स्वागत

लखनऊ। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति, उत्तर प्रदेश ने ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा द्वारा बिना कारण संविदा कर्मियों को सेवा से न हटाए जाने संबंधी दिए गए निर्देशों का स्वागत करते हुए पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से पिछले ढाई वर्षों में हटाए गए लगभग 25 हजार संविदा कर्मियों को तत्काल सेवा में वापस लेने की मांग की है। संघर्ष समिति के केंद्रीय पदाधिकारियों ने कहा कि वर्ष 2017 में जारी आदेश के अनुसार शहरी क्षेत्रों के विद्युत उपकेंद्रों पर 36 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के उपकेंद्रों पर 20 संविदा कर्मियों की व्यवस्था निर्धारित

की गई थी। इसी व्यवस्था के आधार पर वर्षों तक प्रदेश की विद्युत आपूर्ति प्रणाली सुचारु रूप से संचालित होती रही। समिति का आरोप है कि अक्टूबर 2024 से कथित ध्मेनपावर रेशनलाइजेशन और निजीकरण की तैयारी के नाम पर बड़े पैमाने पर संविदा कर्मियों को हटाने का अभियान शुरू किया गया। समिति के अनुसार नवंबर 2024 में पूर्वोच्चल और दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगमों के निजीकरण की प्रक्रिया की घोषणा के बाद संविदा कर्मियों की संख्या में कटौती तेज कर दी गई। संघर्ष समिति ने कहा कि नए टेंडरों में निर्धारित मानकों की अनदेखी करते हुए शहरी क्षेत्रों में

36 के स्थान पर 18.5 तथा ग्रामीण क्षेत्रों में 20 के स्थान पर 12.5 संविदा कर्मियों का प्रावधान किया जा रहा है। वहीं, लखनऊ सहित जिन क्षेत्रों में वॉटिकल रिस्ट्रक्चरिंग लागू की गई है, वहां शहरी क्षेत्रों में यह संख्या घटाकर 7.5 कर दी गई है। इसके चलते बड़ी संख्या में अनुभवी संविदा कर्मी सेवा से बाहर हो गए हैं, जिनमें ऐसे कर्मचारी भी शामिल हैं जिन्होंने 20 से 25 वर्षों तक विद्युत व्यवस्था के संचालन और रखरखाव में योगदान दिया है। समिति ने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में प्रदेशभर में 25 हजार से अधिक संविदा कर्मियों की सेवाएं समाप्त की जा चुकी हैं। साथ ही 55 वर्ष की

आयु पूरी होने पर संविदा कर्मियों को अनिवार्य रूप से हटाने के निर्णय को भी अन्यायपूर्ण और अमानवीय बताया गया। समिति ने कहा कि अनेक कर्मचारी बिजली व्यवस्था को बनाए रखने के दौरान दुर्घटनाओं में घायल हुए, फिर भी उन्हें सेवा से बाहर कर दिया गया। संघर्ष समिति का कहना है कि भीषण गर्मी के बावजूद विद्युत आपूर्ति में आने वाले फॉल्टों को ठीक करने वाले अनुभवी संविदा कर्मियों की संख्या लगातार कम की गई है, जिससे उपभोक्ताओं

को लंबे समय तक बिजली बाधित रहने की समस्या का सामना करना पड़ रहा है और नियमित कर्मचारियों पर कार्यभार बढ़ गया है। समिति ने मांग की कि ऊर्जा मंत्री के निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2017 के निर्धारित मानकों की बहाली करते हुए सभी हटाए गए संविदा कर्मियों को तत्काल सेवा में वापस लिया जाए तथा विद्युत वितरण व्यवस्था में आवश्यक मानव संसाधन उपलब्ध कराकर प्रदेश की बिजली व्यवस्था को और मजबूत बनाया जाए।

भाजपा कार्यालय पर हुई जन सुनवाई: प्राथमिकता से कराया जायेगा समस्याओं का समाधान- अभिषेक कुमार

दैनिक बुद्ध का संदेश



बस्ती। जन समस्याओं के प्रभावी निस्तारण हेतु भारतीय जनता पार्टी द्वारा जन सुनवाई कार्यक्रमों का चरणबद्ध आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में बुधवार को जिला महामंत्री अभिषेक कुमार, जिला उपाध्यक्ष अखंड प्रताप सिंह ने पार्टी कार्यालय पर आये मामलों या फोन पर आये समस्याओं को निःस्वच्छता, जल निकासी, अतिक्रमण नियंत्रण एवं जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों की नियमित निगरानी करने तथा अगली समीक्षा बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नगर निगम का उद्देश्य नागरिकों को बेहतर सुविधाएं एवं उपलब्ध कराना है और सभी अधिकारियों को इस दिशा में पूरी जिम्मेदारी के साथ कार्य करना चाहिए।

निस्तारण हेतु प्रतिबद्ध है। सदैव प्रयास रहता है कि लोगों को सरकार के कल्याणकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे और उन्हें असुविधा न होने पाये। इसके बावजूद यदि किसी की समस्या का समाधान न हो रहा है तो वे भाजपा पार्टी कार्यालय पर आकर अपनी बात बता सकते हैं। पार्टी पदाधिकारी और कार्यकर्ता समाधान के लिये हर स्तर पर पहल करेंगे। कहा कि इस जन सुनवाई से लोगों की सामान्य समस्या बिजली, पानी, सड़क आदि के मामले प्राथमिकता से सुलझ जायेंगे। बताया कि जन सुनवाई में जो मामले आये थे उसके निस्तारण की पहल कर दिया गया है।



